पंचायती राज पब्लिक वर्क्स के ठेकों पर बाहुबलियों का कब्ज़ा

फरीदाबाद (म.मो.) अब तक सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश इस मामले में बदनाम था कि वहां बाहुबली और अपराधी लोग़ हथियारों के बल पर ठेके लेते हैं और उन पर या तो खुद काम करवाते हैं अथवा अच्छी-खासी रकम लेकर उन्हें बेच देते हैं। लेकिन अब यही काम हरियाणा में भी हो रहा है। यहां भी अपराधी एवं दबंग लोग हथियारों के जोर पर इकों का अपहरण करने में लगे हुए हैं। इस तरह का एक मामला अभी हाल में सामने आया है। पृथला से विधायक रघुवीर तेवतिया ने यह घोषणा कर दी है कि इस विधानसभा क्षेत्र के जो ठेके होंगे वे उन्हीं के लोग लेंगे। 27 अप्रैल को 29 गांवों की गलियां बनाने के लिए करीब तीन करोड़ के टेंडर भरे जा रहे थे। इसमें दयालपुर का यशपाल हुड्डा अर्नेस्ट मनी यानी धरोहर राशि जमा कर टेंडर खरीद कर चला गया। दोपहर बाद जब वह टेंडर जमा करने आया तो जनौली गांव के बाहुबलियों ने उसका टेंडर फार्म फाड़ दिया और उसे मारपीट कर भगा दिया। विदित है कि रघुवीर तेवतिया विधायक जनौली गांव का ही निवासी है। उसने कहा कि उसकी मर्जी के बगैर कोई टेंडर नहीं भर सकता और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा, उसे सबक सिखा दिया जायेगा ताकि वह समझ ले कि टेंडर भरने का मतलब क्या होता है। पलवल से करण दलाल के आदमी भी टेंडर भरने आये थे। उनकी कद-काठी और हैसियत को देखते हुए रघुवीर तेवतिया ने उनसे समझौता कर लिया कि वे अपने इलाके पलवल में ठेके लें और वे अपने इलाके में लेंगे। दोनों एक-दूसरे के इलाके में दखल नहीं देंगे।

रघुवीर तेवतिया ने अपने लोगों से कहा कि जो भी ठेके निकलें, उसे तुम लोग लो और अगर पैसे न हों तो उनसे ले। दूसरा कोई ठेके नहीं ले सकता। कुछ सामान्य ठेकेदार तो इस तरह का मामला देख कर वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। बाकी यशपाल हुड्डा ने अपनी जो धरोहर राशि जमा करा दी थी, वह तो गई। उल्लेखनीय है कि इस तरह का काम लगातार जारी है। सुनने में तो यह भी आया है कि अधिकारी अपने भाई-भतीजों के नाम ठेके भी दिलवा देते हैं। इस तरह नेता और अफ़सर दोनों मिल कर ठेके के नाम पर लूट मचाने में लगे हैं। जाहिर है, ये लोग काम करवाने के नाम पर लूट मचाते हैं, इसलिए काम की कोई गुणवत्ता रह नहीं जाती है। किये गये कार्य की गुणवत्ता से किसी को लेना-देना भी नहीं है। खास बात यह है कि यह ठेकों की लूट का काम ठीक प्रशासन की नाक के ऊपर हो रहा है।

प्रशासन को इसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इस गड़बड़झाले में पंचायती राज के अफ़सरान लगे हुए हैं, वे भी अपने बेनामी ठेके चलाते हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि रोहतक में मुख्यमंत्री हुड्डा के परिवार और उनके रिश्तेदारों के नाम ठेके जारी होते हैं। इस तरह सत्ताधारियों और अधिकारियों के संरक्षण में बाहुबली और नेता ठेकों की लूट में लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस तरह के ठेके लेने के लिए बाहुबलियों के बीच हथियारबंद संघर्ष होते हैं और कई लोगों की जाने जाती हैं। इस मामले होने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में जो ईमानदारी अधिकारी आवाज उठाते हैं, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बिहार में जीटी रोड के फोर लेन करने की जिस योजना पर काम जारी है, उसमें ठेकेदारों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के खिलाफ़ आवाज उठाने पर एक काबिल इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की बरसों पहले दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। हरियाणा अभी तक एक ऐसा राज्य बना हुआ है जहां नक्सलियों की घुसपैठ नहीं हुई है। अगर यही स्थिति बनी रही तो नक्सलियों को राज्य में प्रवेश करने का मौका मिल सकता है। खास बात यह है कि ठेके इसलिए जारी किये जाते हैं कि लोग कम से कम लागत पर अच्छी गुणवत्ता वाला काम कर सकें। पर अपराधियों और बाहुबलियों का वर्चस्व इस मामले में होने पर ठेके मनमानी दरों पर तो उठते ही हैं, काम भी घटिया से घटिया होता है।

गर्मी के साथ बढ़ता बिजली संकट

जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बिजली-संकट भी बढ़ता जा रहा है। इसका कोई समय निश्चित नहीं है कि कब बिजली आयेगी और कब जायेगी। बिजली एक बार जाती है तो फ़िर घंटे-दो घंटे तक उसके दर्शन नहीं होते। इससे आम जनता तो तबाह है ही, उद्योग जगत भी काफ़ी परेशान है। बिजली नहीं होने की मार सबसे ज्यादा वे लोग़ झेल रहे हैं जो छोटे-मोटे वर्कशॉप चलाते हैं। उनके पास इतना साधन नहीं कि बड़े-बड़े जेनरेटर रख सकें। वे तो पूरी तरह बिजली के भरोसे ही हैं पर लगातार बिजली कट से वे परेशान हैं और मुनाफा क्या, उनका मेहनताना भी नहीं मिल पा रहा है।

सबसे बुरा हाल तो गांवों का है जहां मात्र चार घंटे बिजली मिल रही है। शहरों को 20 घंटे बिजली देने की घोषणा की गई थी, पर मिल रही है मात्र 12 घंटे। उद्योगों को बिजली आठ घंटे मिल रही है। ऐसे में सभी बिजली की कमी से परेशान हैं।

हरियाणा आर्थिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ा हुआ राज्य है। यहां के कई शहर उद्योगों के केंद्र हैं। फ़िर यहां बिजली का इस तरह आना-जाना समझ में नहीं आता। अगर हरियाणा में बिजली की यह हालत है तो समझा जा सकता है कि देश के पिछड़े राज्यों की स्थिति क्या होगी? बहरहाल, मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि वे राज्य में बिजली की किल्लत नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि वे महंगी से महंगी दर पर बिजली खरीद कर उपलब्ध कराऊंगा। पर चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री अपनी यह घोषणा भूल गये। हरियाणा में जरूरत के मुताबिक बिजली-उत्पादन कम है। और जो है भी, उसका समुचित वितरण नहीं हो पाता। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है। अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक निकम्मे और अयोग्य हैं। नये ट्रांसफार्मर की जगह पुराना माल रिपेयर कर लगाते हैं और उपभोक्ताओं को यह भी खिलाते हैं कि बिजली चोरी कैसे की जाये।

मिर्जपुर कांड : नाकारा सरकारी मशीनरी का फ़ल

हिसार (म.मो) जिले के थाना नारनौंद इलाके में स्थित गांव मिर्जपुर में इस सप्ताह हुए दंगे में दलित परिवार की एक बेटी व उसके पिता का ज़िंदा जल जाना तथा उनकी बस्ती के अनेकों घरों को आग के हवाले कर देने के पीछे जहां तक एक ओर बढ़ती जातीय राजनीति है वहीं पूरी तरह से नाकारा हो चुकी सरकारी मशीनरी है।

जातियों को आधार बना कर राजनीति की शतरंज खेलने वालों के लिए, इस तरह के दंगों में मरने व मारने वाले, शतरंज के मोहरों से अधिक कुछ नहीं होते। लगभग सभी राजनीतिक दल विभिन्न जातियों को अपने-अपने वोट बैंक में परिवर्तित करने के लिए कुछ भी करने को सदैव तत्पर रहते हैं। उन्हें समाजहित व देशहित से कुछ लेना-देना नहीं होता।

महज इत्तफ़ाक की बात है कि यह दंगा अथवा झगड़ा जाटों व बाल्मीकियों के बीच हुआ। यह झगड़ा जाटों का जाटों या बाल्मीकियों का बाल्मीकियों से भी हो सकता था। इस तरह के झगड़ों की रोकथाम को रोकने का पूरा दायित्व अरबों रुपया डकारने वाली सरकारी मशीनरी का है जो अब पूर्णतया नाकारा हो चुकी है। इस मशीनरी में लगे सभी छोटे-बड़े पुर्जे (कर्मचारी व अफ़सरान) पूरी तरह से निकृष्ट हो चुके हैं। दरअसल इन लोगों की भर्तियां व नियुक्तियां योग्यता के आधार पर न होकर अन्य सभी आधारों पर होती हैं।

बेशक इस कांड को जातीय रंग दिया जा रहा है लेकिन वास्तव में यह एक गुंडागर्दी का नमूना है। महज इत्तफ़ाक की बात है कि यह दंगा अथवा झगड़ा जाटों व बाल्मीकियों के बीच हुआ। यह झगड़ा जाटों का जाटों या बाल्मीकियों का बाल्मीकियों से भी हो सकता था। इस तरह के झगड़ों की रोकथाम को रोकने का पूरा दायित्व अरबों रुपया डकारने वाली सरकारी मशीनरी का है जो अब पूर्णतया नाकारा हो चुकी है। इस मशीनरी में लगे सभी छोटे-बड़े पुर्जे (कर्मचारी व अफ़सरान) पूरी तरह से निकृष्ट हो चुके हैं। दरअसल इन लोग़ों की भर्तियां व नियुक्तियां योग्यता के आधार पर न होकर अन्य सभी आधारों पर होती हैं। इस तरह के भर्ती लोग काम में तो नाकारा होते ही हैं, अपने ऊपरवालों की परवाह भी कम ही करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण उस थाने का एसएचओ था, जिसने 2 दिन पहले से वहां चल रहे तनाव का संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा मात्र 20 किलोमीटर दूर तहसील मुख्यालय (हासी)पर बैठे अधिकारी भी वहां व्याप्त तनाव का संज्ञान लेने में असमर्थ रहे। यदि ये लोग समय पर थोड़ी सी हिल डुल कर लेते तो यह सब बखेड़ा न होता।

लेकिन अब हो चुके इस बखेड़े की पुनरावृति रोकने पर किसी का न तो ध्यान है न कोई ठोस योजना। यदि कुछ है तो केवल मगरमच्छ के सियासी आंसू। सबको अपनी-अपनी दुकान रूपी पार्टी के लिए वोट बैंक की चिंता है। और तो और बूटा सिंह भी वहां पहुंच गया, वह भी वहां जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ करके इस घटना को कलंक की संज्ञा दे रहा है। ठीक है, घटना तो कलंक है ही, पर बूटा सिंह खुद क्या किसी कलंक से कम है जो हरिजनों की आड़ में अपनी दुकान चला रहा है।

लगभग सभी पार्टियों के नेता, खासकर हरिजनों के ठेकेदार होने का दावा करने वाले नेता तो वहां पहुंचे ही पहुंचे। ऐसे में भला राहुल गांधी कहां पीछे रहने वाले थे। जब वे यूपी, बिहार, एमपी तक के हरिजनों के घरों में रात बिताने पहुंच सकते हैं तो हरियाणा के इस मामले को कैसे औरों की झोली में जाने दे सकते थे। लिहाज़ा अपने चिर परिचित अंदाज में वहां पहुंच गए तथा अन्य हरिजन नेताओं द्वारा कमाए पुण्य को क्षण भर में लूट कर ले गए।

पानी के लिए त्राहि-त्राहि

नगर निगम अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर में पानी की समस्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। नलों में पानी के न आने और बिजली के कट पर कट लगने से आम जनता इस कदर तबाह हो गई जिसका वर्णन करना मुश्किल है। पानी की समस्या से परेशान लोग़ रोज ही नगर निगम के दफ़्तर पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, पर निगम पदाधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कई इलाकों में सप्लाई को जो पानी आता है, वह पीने लायक क्या, नहाने और बर्तन धोने लायक भी नहीं होता। पानी का रंग लगभग काला होता है। ऐसे पानी के नमूने के साथ लोग़ नगर निगम के दफ़्तर पर पहुंच चुके हैं, पर उनकी समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। ऐसे में लोग़ पानी के लिए कहां भटकें, वह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। ले-दे कर एक ही सहारा है पानी के निजी टैंकरों का। पानी के निजी टैंकर जब आते हैं तो लोग़ों में पानी खरीदने की होड़ मच जाती है। पानी का संकट देखते हुए टैंकर वालों नें भी पानी के भाव बढ़ा दिये हैं। लेकिन 'मरता क्या न करता।' ऊंची कीमत पर भी लोग़ों को पानी खरीदना पड़ता है, क्योंकि इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। नगर निगम की आशा लोग़ों ने अब छोड़ दी है। हां, अगर कभी टैंकर के आने में देर हो जाये तो लोग़ों की परेशानी देखते ही बनती है। सभी लोग़ों को अपनी-अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल। कई घरों से तो महिलायें भी काम पर जाती हैं। पानी नहीं आने अथवा देर से आने से लोग़ों की पूरी दिनचर्या ही अस्त-व्यस्त हो जाती है।

सवाल यह उठता है कि सभी परिस्थितियों से वाकिफ़ होने के बावजूद नगर निगम पानी सप्लाई की उचित व्यवस्था क्यों नहीं करता? पानी टैक्स तो वह वसूल कर लेता है, पर पानी देने में उसकी नानी मरने लगती है। अगर नगर निगम का यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पानी के लिए लोग़ सड़कों पर उतर जायेंगे और तब उन्हें नियंत्रित कर पाना सरकार और निगम प्रशासन के लिए मुश्किल होगा। आखिर, लोग़ों की सहन-शक्ति की एक सीमा होती है।

सवाल खड़ा होता है कि नगर निगम पानी की ढंग से आपूर्ति क्यों नहीं कर पाता? कई जगह पानी की लाइनें टूट गई हैं, कई जगह टूटी हुई लाइनों से सीवर की लाइन मिल गई हे और इस तरह जो पानी लोग़ों को मिलता है भी वह विषाक्त होता है। नगर निगम में सारा काम काग़ज़ों पर चलता है। काग़ज़ों पर ही पाइपें ठीक कर दी जाती हैं। काग़जों पर ही गंदे पानी की जगह साफ़ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाती है। यानी सारी समस्या का हल काग़ज़ों पर ही कर दिया जाता है।

दरअसल, नगर निगम कर्मियों में किसी भी काम को कर पाने की इच्छाशक्ति का अभाव है। दूसरी बात, ये ऐसा काम ही हाथ में लेना चाहते हैं जिसमें इन्हें दो पैसे की नाजायज आमदनी दिखाई पड़े। तीसरी बात, ये इतने नाकाबिल और नाकारा हैं कि चाह कर भी सही ढंग से काम को कर नहीं सकते। इसलिए चुपचाप आराम फर्माते रहते हैं। हां, ये हिलते-डुलते तब हैं जब इन्हें सिक्कों की खनखनाहट सुनाई पड़ती है। पर चूंकि काम करने की योग्यता का इनमें अभाव है, इसलिए ये कुछ करते भी हैं तो उलटा-सीधा कर देते हैं। नगर निगम के एक पूर्व आयुक्त ने यह दावा किया था कि वे पानी की समस्या को दूर कर देंगे। उन्होंने डबुआ कॉलोनी के पास 'आर ओ' सयंत्र भी लगवाया ताकि लोगों को मीठा और शुद्ध पेयजल मिल सके। पर वह 'आर ओ' संयत्र कभी ठीक से चल नहीं सका। सयंत्र ठीक से क्या चलता, सामान्य पानी की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप लोग़ प्राइवेट टैंकरों पर आश्रित हैं और रहेंगे। यही हाल सभी कालोनियों का है। एनएच नंबरों में पानी की आपूर्ति थोड़ी-बहुत होती भी है तो वह पानी इतना खारा होता है मानो उसमें नमक मिला दिया गया हो। उस पानी के इस्तेमाल से जल्द ही बाल पकने लगते हैं और अगर उसे किसी तरह पीने के काम में लाया जाये तो कुछ समय में पेट में पथरी बनना तय है। इधर पिछले बीसियों वर्षों से रैनीवेल परियोजना से पानी मुहैया कराने के लिए इस पर सैंकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये। पर इससे पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका। अब तो लोग़ यह उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि उन्हें रैनीवेल का पानी मिलेगा।

लोग़ मजबूरी में पानी खरीद रहे हैं। पानी प्रकृति का वरदान है। इसी पर मनुष्यों के साथ ही सभी जीव-जंतुओं का अस्तित्व कायम है। यह विडंबना ही है कि प्रकृति के इस वरदान को मोल लेना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में एक दिन जनता का धैर्य चुकना ही है। जब तक जनता शांत है तब तक अधिकारी खूब मौज ले लें, पर जनता के असंतोष और गुस्से का ज्वालामुखी जब फटेगा तब क्या होगा, इसे नगर निगम अधिकारी भी समझते होंगे।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06